PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 015
दि. 15.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

₹27 हजार करोड़ बैंक फ्रॉड की आंच में अनिल अंबानी समूह, सीबीआई की देशभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई से कॉरपोरेट जगत में हलचल

देश के कॉरपोरेट और बैंकिंग जगत में गुरुवार को उस समय बड़ा भूचाल आ गया, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी Central Bureau of Investigation ने उद्योगपति Anil Ambani के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह से जुड़े मामलों में देश के कई शहरों में एक साथ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। मुंबई, गुरुग्राम और बंगलूरू सहित सात प्रमुख परिसरों पर हुई इस कार्रवाई ने न केवल कारोबारी हलकों में हलचल पैदा कर दी, बल्कि हजारों करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच को भी एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया।

सीबीआई की यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और समूह की अन्य वित्तीय कंपनियों से जुड़े मामलों में की गई। एजेंसी के अनुसार, छापेमारी उन वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के परिसरों पर केंद्रित थी, जिन्होंने वर्ष 2015 से 2017 के बीच कंपनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थीं। जांच एजेंसी ने जिन लोगों को निशाने पर लिया, उनमें तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कई अन्य निदेशक शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों की भूमिका वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग संचालन और फंड उपयोग से जुड़े निर्णयों में अहम मानी जा रही है।

सीबीआई ने स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई मुंबई स्थित विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। एजेंसी के अधिकारियों ने कई घंटों तक दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से संबंधित सामग्रियों की गहन जांच की। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी अब फोरेंसिक और वित्तीय जांच की जाएगी। एजेंसी का मानना है कि इन दस्तावेजों से फंड ट्रांसफर, ऋण उपयोग और कथित अनियमितताओं की परतें खुल सकती हैं।

यह मामला केवल एक कंपनी या सीमित वित्तीय गड़बड़ी तक सीमित नहीं माना जा रहा। सीबीआई के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और Life Insurance Corporation of India यानी एलआईसी से प्राप्त शिकायतों के आधार पर रिलायंस एडीए समूह के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में कुल सात अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और बैंक धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 27,337 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इतनी बड़ी रकम से जुड़े आरोपों ने इस पूरे प्रकरण को देश के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों में शामिल कर दिया है।

जांच एजेंसियों का मानना है कि संबंधित कंपनियों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों के उपयोग, फंड डायवर्जन और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हो सकती हैं। यही कारण है कि एजेंसियां केवल कागजी जांच तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि उन अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं, जिन्होंने उस अवधि में कंपनियों के संचालन और वित्तीय फैसलों में प्रमुख जिम्मेदारियां निभाईं।

सीबीआई की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी एजेंसी देशभर में 31 स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। हाल ही में Reliance Telecom Limited, Reliance Commercial Finance Limited और Reliance Home Finance Limited से जुड़े मामलों में मुंबई के 17 परिसरों पर भी छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसी अब इन सभी मामलों को आपस में जोड़कर पूरे वित्तीय नेटवर्क और कथित लेन-देन की श्रृंखला को समझने की कोशिश कर रही है।

इस पूरे मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। सीबीआई ने 20 अप्रैल को डी. विश्वनाथ और अनिल कालिया को गिरफ्तार किया था। एजेंसी के अनुसार, दोनों अधिकारी बैंकिंग संचालन और फंड के उपयोग से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभा रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ के आधार पर कई नए तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी अब उन फैसलों की भी जांच कर रही है, जिनके तहत बड़े पैमाने पर ऋण स्वीकृत हुए और बाद में कथित रूप से उनका दुरुपयोग किया गया।

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जांच की निगरानी सीधे Supreme Court of India की देखरेख में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के कारण एजेंसियों पर निष्पक्ष और व्यापक जांच का दबाव बढ़ गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि शीर्ष अदालत की निगरानी में होने वाली जांच में हर दस्तावेज, हर लेन-देन और हर जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका को बेहद गंभीरता से परखा जाता है। यही कारण है कि यह मामला अब केवल आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश की बैंकिंग व्यवस्था और कॉरपोरेट प्रशासन की पारदर्शिता से भी जुड़ गया है।

अनिल अंबानी समूह पहले भी आर्थिक संकट और कर्ज से जुड़े विवादों के कारण चर्चा में रहा है। एक समय देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में गिने जाने वाले रिलायंस एडीए समूह की कई कंपनियां पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय दबाव, कर्ज संकट और दिवाला प्रक्रिया जैसी चुनौतियों से जूझती रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस का पतन भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी कारोबारी गिरावटों में गिना जाता है। दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भारी कर्ज और बाजार में तेजी से बदलते हालातों ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

हालांकि, अब सीबीआई की जांच ने इस संकट को एक नए दृष्टिकोण से देखने की स्थिति पैदा कर दी है। यदि जांच एजेंसियों के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला केवल कारोबारी विफलता का नहीं, बल्कि सुनियोजित वित्तीय अनियमितताओं और बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग का भी बन सकता है। यही वजह है कि बैंकिंग क्षेत्र, निवेशकों और नियामक संस्थाओं की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े बैंक फ्रॉड के आरोप भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पैसा अंततः आम जनता की बचत और करदाताओं के संसाधनों से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि बड़े कॉरपोरेट समूहों द्वारा ऋण के दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आरोप सामने आते हैं, तो इसका असर पूरे वित्तीय तंत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार और जांच एजेंसियों ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

सीबीआई की ताजा कार्रवाई ने यह संकेत भी दिया है कि एजेंसी अब केवल दस्तावेजी जांच तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। जिन अधिकारियों और निदेशकों के परिसरों पर छापेमारी हुई है, उनसे पूछताछ का दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। संभावना जताई जा रही है कि वित्तीय रिकॉर्ड, ईमेल संचार, बैंकिंग ट्रेल और फंड मूवमेंट की विस्तृत जांच के बाद एजेंसी कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है।

फिलहाल देश की नजरें इस हाई-प्रोफाइल मामले पर टिकी हुई हैं। कॉरपोरेट जगत, बैंकिंग क्षेत्र और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि जांच आखिर किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इतना तय है कि 27,337 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड की यह जांच अब देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में शामिल हो चुकी है और इसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।

शराब नीति केस में बड़ा मोड़ : जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को सुनवाई से किया अलग, केजरीवाल समेत कई आप नेताओं पर अवमानना कार्रवाई की तैयारी

दिल्ली की चर्चित शराब नीति मामले की सुनवाई गुरुवार को उस समय नए मोड़ पर पहुंच गई, जब Swarna Kanta Sharma ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में हलचल तेज कर दी है। जस्टिस शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने जा रही हैं और न्यायिक परंपराओं के अनुसार जो न्यायाधीश अवमानना प्रक्रिया प्रारंभ करता है, वह मुख्य मामले की सुनवाई जारी नहीं रख सकता। इसी कारण उन्होंने शराब नीति मामले को आगे की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया, ताकि किसी अन्य जज की पीठ इस पर सुनवाई कर सके।

यह मामला पहले से ही देश की राजनीति और न्यायिक बहस के केंद्र में रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा सुनवाई से अलग होने और अवमानना कार्रवाई शुरू करने के फैसले ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट संकेत दिए कि वह अदालत और न्यायिक प्रक्रिया पर की गई टिप्पणियों को गंभीरता से ले रही हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए अपने बयान में जस्टिस शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली परिस्थितियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि चूंकि वह अवमानना की कार्यवाही शुरू कर रही हैं, इसलिए उचित यही होगा कि मुख्य मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा की जाए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न्यायिक मर्यादा और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, जिन नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सकती है, उनमें अरविंद केजरीवाल के अलावा Manish Sisodia, Durgesh Pathak, Saurabh Bharadwaj, Sanjay Singh और Vinay Mishra के नाम भी शामिल हैं। अदालत का मानना है कि इन नेताओं की कुछ टिप्पणियां और आरोप न्यायपालिका की निष्पक्षता तथा अदालत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। हालांकि अभी इस संबंध में विस्तृत आदेश आना बाकी है, लेकिन जस्टिस शर्मा के बयान के बाद यह लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कानूनी टकराव और तेज हो सकता है।

दरअसल, इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि उस मांग से जुड़ी है, जो अरविंद केजरीवाल की ओर से अदालत में रखी गई थी। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को शराब नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की थी। उनकी ओर से अदालत में कहा गया था कि जस्टिस शर्मा कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी Rashtriya Swayamsevak Sangh के कार्यक्रमों में कई बार शामिल हो चुकी हैं, इसलिए उनसे निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह आरोप सामने आने के बाद मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बहस में भी बदल गया।

कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी जज की निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना बेहद गंभीर विषय माना जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ऐसे में यदि अदालत को लगता है कि किसी टिप्पणी या आरोप से न्यायिक संस्थाओं की गरिमा प्रभावित हो रही है, तो अवमानना कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि जस्टिस शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए अवमानना प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया।

दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा मामला पहले से ही राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जांच एजेंसियां इस मामले में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और नीति निर्माण में पक्षपात जैसे आरोपों की जांच कर रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है, जबकि विपक्षी दल और जांच एजेंसियां इसे गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ा मामला बता रही हैं। इसी बीच अदालतों में चल रही सुनवाई भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।

"यह बुलडोजर वाला राज्य नहीं" : चुनाव बाद हिंसा पर हाईकोर्ट में ममता की भावुक दलील, बंगाल सरकार को सख्त निर्देश

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चुनाव बाद हिंसा के आरोपों और अदालत की सख्त टिप्पणियों के कारण राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। गुरुवार को Calcutta High Court में हुई सुनवाई के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज कर दी। चुनाव परिणामों के बाद कथित हिंसा, धमकी और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक विचारधारा या दलगत जुड़ाव के आधार पर घर या व्यवसाय से बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई इलाकों से हिंसा और टकराव की खबरें सामने आने का दावा किया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश Sujay Paul और न्यायमूर्ति Partha Sarathi Sen की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को चुनाव बाद की हिंसा रोकने के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। अदालत ने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और किसी भी नागरिक को राजनीतिक पहचान के आधार पर डराने, धमकाने या विस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इस सुनवाई का सबसे चर्चित पहलू वह रहा, जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री Mamata Banerjee स्वयं अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से वकील के रूप में उपस्थित हुईं और उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत कक्ष में उन्होंने कहा कि चुनाव बाद की हिंसा से राज्य का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं और बच्चे भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि पुलिस पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही और कई इलाकों में लोगों को

संरक्षण की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने अदालत से कहा, "यदि अदालत अनुमति दे तो मैं अतिरिक्त हलफनामे में इन घटनाओं और आरोपों का विस्तार से उल्लेख करूंगी। राज्य के लोगों को बचाइए। यह 'बुलडोजर' राज्य नहीं है। यह पश्चिम बंगाल है।" अदालत कक्ष में उनकी यह टिप्पणी बेहद चर्चा में रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि "बुलडोजर राज्य" शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों की राजनीति पर निशाना साधने की कोशिश की, जहां अपराध और अतिक्रमण के मामलों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहस होती रही है। ममता बनर्जी ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी भी नागरिक को उसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों के बाद कई क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है और लोग खुलकर शिकायत दर्ज कराने से भी डर रहे हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील Dhiraj Trivedi ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अदालत में कहा कि याचिका में चुनाव बाद की हिंसा के ठोस और विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि केवल बड़ी संख्या में शिकायतों का दावा कर देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अदालत के सामने स्पष्ट घटनाएं, पीड़ितों का विवरण और तथ्यात्मक सामग्री रखनी आवश्यक होती है। त्रिवेदी ने कहा कि याचिकाकर्ता 2,000 से अधिक शिकायतों का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक भी मामले का स्पष्ट विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद भी चुनावी हिंसा से संबंधित एक बड़ा मामला अदालत में आया था, जिसकी सुनवाई पांच-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने की थी। इसलिए यदि इस मामले में भी गंभीर संवैधानिक और प्रशासनिक प्रश्न उठते हैं, तो इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेजने पर विचार किया जा सकता है।

मितव्ययिता मोड में सरकारें : ईंधन बचत के बहाने क्या देश को बड़े आर्थिक संकट के लिए किया जा रहा तैयार?

देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में इन दिनों जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वे सामान्य सरकारी अभियान से कहीं अधिक गहरी कहानी बयान करती नजर आ रही हैं। कहीं मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल पर विधानसभा पहुंच रहे हैं, कहीं मंत्री पैदल मंत्रालय जा रहे हैं, तो कहीं सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या घटाई जा रही है, एसी के तापमान तय किए जा रहे हैं, विदेश यात्राओं पर रोक लगाई जा रही है और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ईंधन बचत, आयात नियंत्रण और घरेलू संसाधनों के संरक्षण पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में राजनीतिक और आर्थिक हलकों में यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या यह केवल प्रतीकात्मक सादगी अभियान है या फिर देश को धीरे-धीरे आने वाले किसी बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा ईंधन बचाने की अपील के बाद केंद्र और कई राज्य सरकारों ने जिस तेजी से फैसले लेने शुरू किए, उसने इस पूरी कवायद को और अधिक गंभीर बना दिया है। आम तौर पर सरकारें बचत और सादगी की बातें करती रही हैं, लेकिन इस बार जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे केवल भाषणों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहे। राज्यों में मंत्रियों और अधिकारियों के व्यवहार में अचानक आया बदलाव यह संकेत दे रहा है कि सरकारें संसाधनों के उपयोग को लेकर बेहद सतर्क हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की तस्वीरों ने बटोरी। Devendra Fadnavis गुरुवार को अपने सरकारी आवास 'वर्षा' से मोटरसाइकिल पर विधान भवन पहुंचे। उनके साथ भाजपा नेता और मंत्री Ashish Shelar भी मौजूद थे। राजनीतिक हलकों में इसे प्रतीकात्मक संदेश माना गया कि सरकार अब ईंधन बचत को केवल सलाह नहीं, बल्कि व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहती है। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री Nitesh Rane मंत्रालय तक पैदल पहुंचे और बैठक में हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने मंत्रियों के काफिलों में वाहनों की संख्या आधी करने, विदेश दौरों पर रोक लगाने और गैर-जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती के निर्देश जारी किए हैं। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने इतने व्यापक स्तर पर सरकारी खर्चों और ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में एक साथ कई फैसले लिए हैं।

यह बदलाव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा। राजधानी दिल्ली में भी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सरकारी विभागों के लिए सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 50 प्रतिशत बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने, विभागों के ईंधन कोटे में 20 प्रतिशत कटौती करने और मंत्रियों-विधायकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मेट्रो और डीटीसी बसों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि सरकारी वाहनों की निर्भरता कम की जा सके। आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह के संकेत दिखाई दिए। मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu, उपमुख्यमंत्री Pawan Kalyan और मंत्री Nara Lokesh ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत घटाने का निर्णय लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के फैसले केवल खर्च कम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जनता को यह संदेश भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में संसाधनों का संयमित उपयोग आवश्यक हो सकता है।

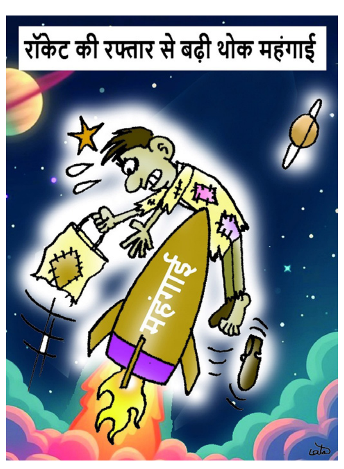

संपादकीय

दवा नहीं दिल में खोट

पिछले दिनों सामने आई वह खबर विचलित कर गई कि दिल और रक्तचाप नियंत्रण की दवाइयों में गुणवत्ता की गिरावट पायी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ की ओर से मार्च माह के लिए जारी ड्रग अलर्ट में देश में बनी कई दवाइयों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट डराती है कि कुल 141 दवाओं के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें शुगर, हार्ट, उच्च रक्तचाप, मिर्गी जैसे गंभीर रोगों का उपचार करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। इनमें इंजेक्शन व कफ सिरप भी शामिल हैं। कमोबेश यही स्थिति विटामिन व आयरन की गोलियों की भी रही। जिन राज्यों में उत्पादित घटिया दवाओं का खुलासा हुआ, उनमें हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर रहा, फिर उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आदि राज्य शामिल हैं। यानी एक-दो राज्य नहीं, तमाम राज्यों के दवा उत्पादक इस अपवित्र कर्म में शामिल हैं। यूं कहें कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है। विडंबना देखिए कि कफ सिरप के 17 नमूने फेल हुए हैं। अब यह साफ हो गया कि अफ्रीका व सेंट्रल एशिया के कुछ देशों तथा भारत के कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के जो आरोप भारतीय दवा कंपनियों पर लगे थे, वे गलत नहीं थे, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय दवा उद्योग की छवि खराब हुई। इतना ही नहीं, टूथपेस्ट, मेहंदी व साबुन के नमूने तक फेल हुए हैं। कह सकते हैं कि दवा के नाम पर दर्द देने का कारोबार देश के विभिन्न भागों में खूब फल-फूल रहा है, जो नियामक एजेंसियों की कारगुजारियों पर सवाल उठाता है। कह सकते हैं कि यह अब सिर्फ स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं रहा, यह जिंदगियों से खिलवाड़ के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाता है।

निस्संदेह, घटिया दवाओं से किसी का बीमार होना एक व्यक्ति या परिवार की ही त्रासदी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कोई व्यक्ति सेहत सुधारने के लिए महंगी दवा का सेवन करे और उपचार के बाद और बीमार हो जाए। ये मरीज के विश्वास के साथ भी छल जैसा है। यह देश में सक्रिय खतरनाक तंत्र की ओर भी इशारा है जो पूरे देश में नकली व घटिया दवाओं के उत्पादन व आपूर्ति से जुड़ा है। वे चिकित्सक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते जो ऐसी संदिग्ध दवाइयां मरीजों के उपचार के लिए लिखते हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर शंका रहती है। कोरोना काल में हमने देखा था कि चंद रुपयों के लालच में घातक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे गए। कितना शर्मनाक है कि जानलेवा कैंसर की दवाइयों में घटिया व सस्ती एंटी-फंगल दवा मिलाकर बेची जा रही थी। गुरुग्राम में पिछले दिनों वजन घटाने वाले नकली इंजेक्शनों की बड़ी खेप बरामदगी हुई। देश में घातक दवाओं को बेचने वाला एक तंत्र सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। कोई मरे या जीए, उनकी बला से। उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब है। दरअसल, यह संकट एक राज्य का नहीं, पूरे देश के सामने मौजूद है। नियामक एजेंसियों की लापरवाही, कड़े कानूनों का अभाव व दोषियों को समय पर कड़ी सजा न मिलना इस अमानवीय धंधे के फलने-फूलने की वजह बन रहा है। निस्संदेह मानवता के खिलाफ होने वाले इस आपराधिक कृत्य में चिकित्सा तंत्र से जुड़े लोगों की भूमिका भी होगी। घटिया दवाओं का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यवस्था में शामिल काली भेड़ें इस अपवित्र कारोबार को प्रश्रय दे रही हैं। निगरानी तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाकर और कानून के क्रियान्वयन में तेजी लाकर ही स्थिति को संभाला जा सकता है। आज देश में उपभोक्ताओं व मरीजों के तिमारदारों को जागरूक करने की जरूरत है कि वे दवा खरीदते समय मेडिकल स्टोर से बिल लें। दवाओं की पैकेजिंग की जांच-पड़ताल करें। संदेह होने पर संबंधित विभागों को शिकायत करके राष्ट्रीय दायित्व निभाएं। तभी दवा जीवन रक्षा का माध्यम बनी रह सकेगी।

ट्रंप और जिनपिंग की दोस्ती ने बदल डाले वैश्विक राजनीतिक समीकरण, Quad का भविष्य अधर में

> “ट्रंप की चीन यात्रा ने यह भी साफ कर दिया कि चीन को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है। वहीं बीजिंग ने ट्रंप की इस यात्रा को केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपनी तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन में बदल दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा बदलती विश्व व्यवस्था का ऐसा प्रतीक बनकर सामने आई जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की लंबी बैठकों, व्यापारिक समझौतों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी सहयोग पर चर्चा तथा अमेरिकी उद्योगपतियों की भारी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि तमाम टकरावों और आरोपों के बावजूद अमेरिका और चीन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसी के साथ यह सवाल भी तेज हो गया है कि क्या इस यात्रा ने क्वॉड जैसे रणनीतिक समूहों के भविष्य पर भी अनिश्चितता पैदा कर दी है?

दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, तब ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि “अमेरिका भारत को चीन और रूस के हाथों खो रहा है।” यही नहीं, मोदी की चीन और रूस के नेताओं के साथ तस्वीरों को वाशिंगटन में रणनीतिक असहजता के रूप में देखा गया था। लेकिन अब वही ट्रंप खुद चीन की धरती पर शी जिनपिंग के साथ बैठकों में व्यस्त रहे। उनके साथ अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी मौजूद रहे। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि यदि भारत का चीन से संवाद अमेरिका के लिए “भारत को खो देना” था, तो फिर ट्रंप की अपनी चीन यात्रा को क्या कहा जाए? क्या यह अमेरिकी यथार्थवाद है, आर्थिक मजबूरी है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की नई स्वीकारोक्ति है?

ट्रंप की इस यात्रा ने यह भी साफ कर दिया कि चीन को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है। वहीं बीजिंग ने ट्रंप की इस यात्रा को केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपनी तकनीकी, आर्थिक

और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन में बदल दिया। शहर की सड़कों पर चालक रहित विद्युत वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां, मानवरूपी रोबोट और डिजिटल विज्ञापन चीन की नई ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। चीन दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि अब वह केवल सस्ती वस्तुएं बनाने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाली शक्ति बन चुका है।

देखा जाये तो ट्रंप की यात्रा ऐसे समय हुई जब अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई मोर्चों पर दबाव में है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने ईरान संकट का उपयोग अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच चीन ने ऊर्जा आपूर्ति और हथियारों के जरिये अपनी भूमिका बढ़ाई, जबकि अमेरिका युद्ध और आर्थिक दबावों में उलझा रहा। यही कारण है कि ट्रंप को अंततः बीजिंग पहुंचकर शी जिनपिंग से संवाद करना पड़ा।

बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि यदि ताइवान के मुद्दे को ठीक ढंग से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। यह बयान केवल चेतावनी नहीं था बल्कि बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी था। चीन अब अमेरिका से बराबरी की भाषा में बात कर रहा है।

ट्रंप की प्राथमिकता हालांकि व्यापार और निवेश रही। उनके साथ एलन मस्क, जेन्सन हुआंग और अन्य अमेरिकी उद्योगपति भी पहुंचे। यह इस बात का संकेत था कि अमेरिकी उद्योग जगत चीन से दूरी नहीं चाहता। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और विशाल तकनीकी बाजार से अलग होना अमेरिका के लिए आसान नहीं है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक बयान ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई संवेदनशील मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए। बयान के अनुसार ट्रंप और शी जिनपिंग ने अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बाजार पहुंच बढ़ाने, चीन के निवेश को अमेरिका में प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न होने देने पर भी सहमति जताई। चीन ने जलडमरूमध्य के सैन्यीकरण का विरोध दोहराया, जबकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने पर भी साझा रुख सामने आया। यह बयान इस बात का संकेत है कि तीखी प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद अमेरिका और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर टकराव के बजाय नियंत्रित सहयोग की राह भी तलाश रहे हैं।

यही वह बिंदु है जहां क्वॉड का भविष्य भी सवालों में घिरता दिखाई देता है। क्वॉड को लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाले समूह के रूप में देखा जाता रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी चीन को लेकर साझा रणनीतिक चिंता पर आधारित मानी जाती है। लेकिन यदि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने, व्यापार बढ़ाने और तकनीकी सहयोग तलाशने बीजिंग पहुंचता है, तो फिर क्वॉड की वास्तविक दिशा क्या रह जाएगी?

भारत के लिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली ने क्वॉड को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। लेकिन ट्रंप की चीन यात्रा यह संकेत देती है कि अंततः अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा। यदि आर्थिक या सामरिक कारणों से उसे चीन के साथ समझौता करना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में भारत को यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति स्थायी मित्रताओं से अधिक स्थायी हितों पर चलती है।

ट्रंप की यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं है। यह तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज, चिप निर्माण, समुद्री मार्गों और वैश्विक प्रभाव की व्यापक लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अमेरिका चीन को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी कंपनियां चीन के बाजार और विनिर्माण क्षमता से अलग नहीं हो पा रहीं। दूसरी ओर चीन अमेरिकी तकनीक और वैश्विक वित्तीय संरचना से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।

इसीलिए बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात केवल दो नेताओं की बैठक नहीं थी। यह उस नई विश्व व्यवस्था की झलक थी जिसमें प्रतिद्वंद्विता और सहयोग साथ-साथ चलेंगे। दोनों देश सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चुनौती देंगे, लेकिन आर्थिक और तकनीकी स्तर पर पूरी तरह अलग भी नहीं होंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में भारत की स्थिति बेहद जटिल हो जाती है। एक ओर वह अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है और चीन के साथ संवाद भी बनाए हुए है। ट्रंप की चीन यात्रा भारत को यह संदेश भी देती है कि वैश्विक राजनीति में किसी एक धुरी पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। बहरहाल, ट्रंप की बीजिंग यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की विश्व राजनीति का केंद्र अब अमेरिका चीन संबंध ही होंगे। यही संबंध तय करेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, तकनीकी नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा और भविष्य की विश्व व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन इसके साथ ही यह यात्रा एक बड़ा सवाल भी छोड़ गई है कि यदि अमेरिका खुद चीन के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहा है, तो फिर दुनिया के बाकी देशों से वह किस प्रकार की रणनीतिक निष्ठा की अपेक्षा कर सकता है?

प्रेरणा

परोपकार में छिपा सच्चा देवत्व

मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख, आराम और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बना है। यदि जीवन केवल स्वयं तक सीमित रह जाए, तो उसका महत्व बहुत छोटा हो जाता है। जीवन तब सार्थक बनता है, जब उसमें दूसरों के लिए कुछ करने की भावना जागती है। परोपकार वही शक्ति है, जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रखा, वे समय के साथ भुला दिए गए, लेकिन जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपना तन, मन और समय समर्पित किया, वे आज भी सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किए जाते हैं। मनुष्य के भीतर छिपा हुआ देवत्व तभी प्रकट होता है, जब वह अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने लगता है।

चीनी महान दार्शनिक Confucius की बुद्धिमत्ता और विचारों की चर्चा दूर-दूर तक होती थी। उनके पास केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन को देखने की एक गहरी दृष्टि भी थी। कहा जाता है कि एक दिन चीन के सम्राट ने उनसे प्रश्न किया, “इस संसार में देवताओं से भी महान कौन हो सकता है?” यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि यह जानने की इच्छा भी थी कि महानता का वास्तविक अर्थ क्या है। कन्फ्यूशस मुस्कुराए और बोले, “सत्य को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति महान होता है।” सम्राट इस उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न जाग उठा। उन्होंने फिर पूछा, “क्या कोई ऐसा भी है, जो देवताओं से अधिक महान हो?”

कन्फ्यूशस सम्राट को अपने साथ नगर के बाहर ले गए। वहां एक वृद्ध व्यक्ति पूरी लगन और शांति के साथ कुआं खोद रहा था। उसकी उम्र काफी अधिक थी, शरीर कमजोर दिखाई देता था, फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मिक आनंद की चमक थी। वह अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा था। वह जानता था कि शायद वह इस कुएं का पूरा लाभ स्वयं कभी न उठा सके, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इससे लाभान्वित होंगी। कन्फ्यूशस ने उस वृद्ध की ओर संकेत करते हुए कहा, “महाराज, यही व्यक्ति देवताओं से भी महान है, क्योंकि यह अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर रहा है।”

यह कथा हमें जीवन का एक गहरा सत्य समझाती है। देवत्व किसी चमत्कार, शक्ति या ऐश्वर्य में नहीं छिपा होता, बल्कि दूसरों के लिए जीने की भावना में बसता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, तब वह केवल इंसान नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर ईश्वर के गुण प्रकट होने लगते हैं। संसार में सबसे बड़ी पूजा किसी मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाना है। सबसे बड़ा धर्म किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना है। आज के समय में मनुष्य धीरे-धीरे आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। लोग अपने लाभ और सफलता के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें दूसरों के दुख दिखाई ही नहीं देते। समाज में संवेदनाएं कम होती जा रही हैं। रिश्तों में अपनापन घट रहा है और मनुष्य केवल अपने हित तक सीमित होता जा रहा है।

ऐसे समय में परोपकार का महत्व और भी बढ़ जाता है। परोपकार केवल धन देने तक सीमित नहीं होता। किसी को प्रेम देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी जरूरतमंद को सही मार्ग दिखाना या किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना भी परोपकार ही है। छोटी-छोटी मददें भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं।

परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य के भीतर शांति और संतोष पैदा करता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसके भीतर कभी न कभी खालीपन रह जाता है। चाहे उसके पास कितना भी धन, पद या प्रसिद्धि क्यों न हो, उसका मन संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है, उसे आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। यही आनंद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान और प्रेम बना रहता है।

भारतीय संस्कृति में भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हमारे ऋषि-मुनियों ने हमेशा “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की कामना की। उन्होंने सिखाया कि सच्चा मनुष्य वही है, जो दूसरों के सुख-दुख को अपना समझे। प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। नदियां बिना किसी स्वार्थ के सबकी प्यास बुझाती हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों को देते हैं। यदि प्रकृति केवल अपने लिए जीती, तो संसार का संतुलन कभी बना नहीं रह सकता था। इसी प्रकार मनुष्य भी तभी महान बन सकता है, जब वह दूसरों के लिए उपयोगी बने।

कई बार लोग सोचते हैं कि परोपकार करने के लिए बहुत अधिक धन या शक्ति चाहिए, लेकिन यह सत्य नहीं है। एक गरीब व्यक्ति भी अपने व्यवहार, प्रेम और सहयोग से किसी का जीवन बदल सकता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहां साधारण लोगों ने अपने छोटे-छोटे कार्यों से समाज पर गहरा प्रभाव डाला। किसी घायल व्यक्ति की मदद करना, किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग देना या किसी वृद्ध की सेवा करना भी उतना ही बड़ा कार्य है, जितना कोई विशाल दान देना।

वास्तव में परोपकार मनुष्य को भीतर से ऊंचा उठाता है। यह अहंकार को समाप्त करता है और हृदय को विशाल बनाता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, उसका संसार बहुत छोटा होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका हृदय पूरे समाज को अपने भीतर समेट लेता है। ऐसे लोग मरने के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रहते हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में परोपकार की भावना को फिर से जागृत करें। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ी-सी खुशी लाने का प्रयास करे, तो समाज की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। मानवता का असली सौंदर्य इसी में है कि हम एक-दूसरे के काम आएं। यही वह मार्ग है, जो मनुष्य को केवल सफल नहीं, बल्कि महान बनाता है। परोपकार ही वह प्रकाश है, जो मनुष्य के भीतर छिपे देवत्व को उजागर करता है और उसे साधारण इंसान से ऊपर उठाकर सच्चे अर्थों में पूजनीय बना देता है।

बंगाल में “शुभ राज“ के साथ सनातन का सूर्योदय

पश्चिम बंगाल में 69 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार प्रथम सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कार्यभार ग्रहण करके काम पर लग गयी है। बंगाल में बीजेपी की विजय बहुत बड़ी व ऐतिहासिक है। बंगाल ही नहीं भारत के अन्य भागों में भी इस विजय का आनंद दिखाई वातावरण दे रहा है। इस विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक, तेलंगना और गुजरात के दौरे में जो भीड़ उमड़ रही है उससे स्पष्ट रूप से जनसामान्य और भाजपा कायकर्ताओं के उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनावों मे हिंदू समाज ने पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के विरुद्ध एकजुट होकर मतदान किया और जिसका परिणाम आज पूरा भारत देख रहा है। बंगाल की जिस धरती पर 75 वर्ष पूर्व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की वैचारिक नींव रखी थी उसी बंगाल में पहली बार भाजपा 27 सीटों के साथ सत्ता के शिखर पर पंहुची और भगवा वस्त्रों में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की कैबिनेट में अभी पांच मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई है, जिसमें बंगाल में भाजपा का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप घोष, फैशन डिजाइनर से बंगाल भाजपा की सबसे मुखर नेत्री बनी अग्निमित्रा पॉल जिन्होंने तृणमूल के खिलाफ आक्रामक मोर्चा संभाला, बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे अशोक कीर्तनिया जो उत्तर 24 परगना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे इलाको में भाजपा के जमीनी संगठनकर्ता के रूप मे अत्यंत सक्रिय रहे हैं, छात्र राजनीति से उभरे नेता निशीथ प्रामाणिक जो 2019 में भाजपा से जुड़े और जंगल महल के आदिवासी समुदाय के बड़े नेता खुदीराम टुडू शामिल हैं। अभी इस मंत्रिमंडल है का विस्तार होना बाकी है। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप लघु भारत के भव्य दर्शन हो रहे थे तथा भविष्य की राजनीति के संकेत भी मिल रहे थे।

इसे भी पढ़ेंः अब घुसपैठ से मुक्त होगा पश्चिम बंगाल

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक बंगाल में कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल की सरकारें रहीं जो तुष्टिकरण में आकंठ डूबी रहीं और हिंदुओ को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। स्थितियां इतनी विकट हो गयी थीं कि बंगाल की धरती पर जय श्रीराम बोलने पर नफरत का कहर टूट पड़ता था। आज उसी बंगाल में जब जयश्रीराम के नारे गूंज रहे हैं तो बंगाल का हर सनातनी खुशी से सराबोर हो रहा है। बंगाल में भाजपा सरकार आने से पश्चिम बंगाल के हिन्दुओं को तुष्टिकरण की दमनकारी नीतियों और भय के माहौल से आजादी मिली है। यह विजय केवल सत्ता का परिवर्तन नही अपितु बंगाल के पुनरुत्थान का शंखनाद है। अब बंगाल सही मायने में सोनार बांग्ला बनने की ओर अग्रसर होगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक उत्थान के नए दौर मे प्रवेश करेगा।

हार की कुंठा से ग्रसित तृणमूल व विरोधी दलों के नेता अभी भी एसआईआर, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षाबलों वाले आरोप दोहरा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा ने यह चुनाव लम्बे संघर्ष और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद जीता है। तृणमूल के राज में वर्ष 2011 से 2025 के बीच भाजपा के 321 कार्यकर्ता मारे गए, उनके विरुद्ध हुई हिंसा में हजारों घर उजाड़ दी गए, भाजपा व संघ के किसी कार्यकर्ता को बम से उड़ाया गया किसी को पेड़ से लटकाया गया। 2021 में तो भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति तृणमूल के लोगों ने क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी थीं। नंदीग्राम से लेकर वीरभूम तक, कूच बिहार हो या वशीर हाट चुनाव के बाद बदले के नाम पर पूरे-पूरे गांव खाली करवा दिए गए थे। 2021 की चुनावी हिंसा में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए किंतु ममता सरकार उन सभी में अड़ंगा डालती रही। आज संदेशखाली से आर जी कर कांड तक सभी पीड़ित परिवारों के मन में एक नया सबेरा आया है कि अब न्याय होकर रहेगा। बंगाल के हिंदू जनमानस को नयी सरकार पर भरोसा है इसलिए नई सरकार को भी अत्यंत तत्परता और सतर्कता के साथ संकल्प पत्र को पूरा करना होगा। नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय लिए हैं उनसे उसकी गंभीरता तथा बंगाल की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है।

नई सरकार के पहले फैसले- शुभेंदु मंत्रिपरिषद ने अपनी पहली बैठक में ही कई बड़े निर्णय लिए हैं। जिनमें आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में लागू करना, भारतीय न्याय सहिंता के तीन कानूनों को लागू करना, बीएसएफ को सीमावर्ती क्षेत्रों में 45 दिनों के अन्दर जमीन स्थानांतरित करना शामिल है। ममता बनर्जी की सरकार इन सभी कार्यों में लगातार अड़ंगा ही डालती रही थी।

अभियान

ज्येष्ठ का पुण्यकाल : सेवा, साधना और संवेदना से आत्मकल्याण का मार्ग

भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में समय को केवल दिन, महीने और वर्षों की गणना तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन, प्रकृति और अध्यात्म के साथ गहराई से जोड़ा गया है। वैदिक पंचांग का प्रत्येक महीना अपने भीतर कोई विशेष संदेश, ऊर्जा और आध्यात्मिक महत्व समेटे होता है। इन्हीं महीनों में ज्येष्ठ मास का विशेष स्थान है। यह महीना केवल वर्ष के सबसे गर्म समय का संकेत नहीं देता, बल्कि मनुष्य के भीतर दया, तप, त्याग और परोपकार की भावना को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब सूर्य की तपिश धरती को झुलसा रही होती है, तब यही समय मनुष्य की संवेदनशीलता और धर्मपरायणता की परीक्षा भी बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को सेवा, दान, भक्ति और तपस्या का श्रेष्ठ काल बताया गया है।

‘ज्येष्ठ’ शब्द का अर्थ ही होता है — श्रेष्ठ, बड़ा और वरिष्ठ। यह नाम केवल संयोग नहीं, बल्कि इस महीने के महत्व का प्रतीक है। वैदिक पंचांग के अनुसार, जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा ‘ज्येष्ठा’ नक्षत्र में स्थित रहता है, वही महीना ‘ज्येष्ठ’ कहलाता है। भारतीय ऋषियों ने खगोलीय घटनाओं और मानव जीवन के संबंध को गहराई से समझा था। इसलिए महीनों का निर्धारण केवल समय की गणना नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन के आधार पर किया गया। ज्येष्ठ मास का आगमन यह संकेत देता है कि प्रकृति अपने सबसे कठोर स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है। धरती तप रही होती है, नदियों का जल घटने लगता है और प्रत्येक जीव जल तथा छाया की तलाश में व्याकुल हो उठता है। ऐसे समय में धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करुणा और सेवा का रूप धारण कर लेता है।

इस वर्ष ज्येष्ठ मास का महत्व और भी अधिक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अधिक मास का शुभ संयोग उपस्थित है। सनातन धर्म में अधिक मास को ‘पुरुषोत्तम मास’ कहा गया है और इसे भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। वैदिक पंचांग में चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के मध्य उत्पन्न अंतर को संतुलित करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। यह परंपरा भारतीय ज्योतिष और कालगणना की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करती है। अधिक मास केवल समय का समायोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर माना गया है। इस अवधि में जप, तप, व्रत, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है।

ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्यनारायण और भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य जीवन के आधार हैं। उनका प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा ही इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। इसलिए इस महीने प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सात्विक जीवन का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही, श्रीहरि विष्णु की पूजा मनुष्य के जीवन में संतुलन, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करने से भय, रोग और संकट दूर होते हैं। मान्यता है कि इसी महीने भगवान श्रीराम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इसलिए यह समय भक्ति और शक्ति दोनों का संगम माना जाता है।

सनातन संस्कृति में दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, किंतु ज्येष्ठ मास में दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसका कारण केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना भी है। जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तब जल की एक बूंद भी जीवन के समान मूल्यवान हो जाती है। यही कारण है कि इस महीने जलदान को ‘महादान’ कहा गया है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना, मिट्टी के घड़े रखना या शरबत वितरित करना केवल सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि ईश्वर की सच्ची आराधना मानी जाती है। भारतीय परंपरा में जल को देवस्वरूप माना गया है। जल जीवन है और जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य।

ज्येष्ठ मास में अन्न, वस्त्र, छाते, हाथ के पंखे, मिट्टी के घड़े, सुराही, कूलर, फल और शीतल पेय पदार्थों का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज जैसे रसदार फलों का दान केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सेवा दोनों का संदेश देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में दूसरों के कष्ट को कम करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। आधुनिक समाज में भले ही जीवनशैली बदल गई हो, लेकिन करुणा और परोपकार की आवश्यकता आज भी उतनी ही है। ज्येष्ठ मास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को जल देता है, किसी गरीब को भोजन देता है या किसी असहाय को राहत पहुंचाता है, तब वह केवल पुण्य अर्जित नहीं करता, बल्कि अपने भीतर मानवता का प्रकाश भी जगाता है। यही प्रकाश धीरे-धीरे आत्मा को पवित्र बनाता है। सनातन धर्म का मूल तत्व ही यही है कि ईश्वर की सच्ची पूजा जीवों की सेवा में निहित है।

इस महीने पशु-पक्षियों की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। प्रचंड गर्मी में जब पक्षी आकाश में भटकते हैं और पशु जल के लिए व्याकुल होते हैं, तब उनके लिए जल और भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। घरों की छतों पर पानी के पात्र रखना, पेड़ों के नीचे पक्षियों के लिए दाना डालना और पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना वास्तव में जीवदया का श्रेष्ठ उदाहरण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मूक प्राणियों की रक्षा करता है, उस पर देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदना ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है।

भारतीय संस्कृति में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। ज्येष्ठ मास में पौधारोपण का विशेष महत्व इसी कारण बताया गया है। जब धरती सूर्य की गर्मी से तप रही होती है, तब वृक्ष ही छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार तैयार करता है। पीपल, वट और तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा का विधान भी इसी महीने विशेष रूप से किया जाता है। पीपल को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है, वट वृक्ष को दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक तथा तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इनकी पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है।

कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना और जलाशयों का निर्माण करना भी ज्येष्ठ मास में अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। प्राचीन भारत में जलस्रोतों का निर्माण समाज सेवा का सबसे बड़ा कार्य माना जाता था। आज भी यदि कोई व्यक्ति जल संरक्षण और जल उपलब्धता के लिए प्रयास करता है, तो वह वास्तव में मानवता की सेवा कर रहा होता है। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, इसलिए जल संरक्षण और जलदान दोनों ही धर्म और कर्तव्य माने गए हैं।

ज्येष्ठ मास केवल बाहरी दान और सेवा का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और तपस्या का भी काल है। तप का वास्तविक अर्थ केवल कठिन साधना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और स्वार्थों पर नियंत्रण रखना है। जब मनुष्य अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचने लगता है, तभी उसके भीतर वास्तविक आध्यात्मिकता जन्म लेती है। यही कारण है कि इस महीने जप, ध्यान, व्रत और सात्विक आचरण पर विशेष बल दिया गया है। यह मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में संतुलन लाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य के वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया, राज्य मंत्री श्री प्रवीणकुमार माळी ने सासन गिर में आयोजित समिट में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होगी पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट

▶▶ भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समिट के पूर्वार्ध के रूप में भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक और चंद्रपुर में प्री-इवेंट आयोजित किए जाएंगे

▶▶ सासन गिर में लायन कंजर्वेशन पर प्री-इवेंट आयोजित हुई

▶▶ एशियाटिक लायन-गिर के शावक के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के सफल प्रयासों से प्रधानमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र को साकार किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ वनराज की गौरवशाली विरासत को बनाए रखते हुए वन्यजीवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट लायन' सफल रहा है

▶▶ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए 'जीव में शिव' और 'पौधों में परमात्मा' की संस्कृति का विश्व को दर्शन कराएगी

▶▶ सिंह संरक्षण को प्राथमिकता और वन विभाग की बेहतरीन कार्यप्रणालियों के परिणामस्वरूप सिंहों की संख्या और उनके विचरण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

▶▶ इकोलॉजी के साथ इमोशन जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का दृष्टिकोण गुजरात में चरितार्थ हो रहा है

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 1 जून 2026 को नई दिल्ली में आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा : केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

▶▶ गुजरात का सिंह संरक्षण का उत्कृष्ट रोल मॉडल विश्व के सामने वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, बिग कैट वर्ग की 7 प्रजातियों में से 5 भारत में पाई जाती हैं; यह देश का गौरव है : केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

▶▶ गुजरात की भूमि पर बाघ का स्थायी निवास सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग तैयार है, बरडा सिंहों का दूसरा आवास बन चुका है : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

गांधीनगर, 14 मई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आईबीसीए समिट भारत-2026 के पूर्वार्ध के रूप में सासन गिर में आयोजित पहली 'प्री-इवेंट लायन कंजर्वेशन' का गुरुवार को गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि एशियाटिक लायन यानी गिर के शावकों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के सफल प्रयासों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार किया है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य के वन मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया और राज्य मंत्री श्री प्रवीणकुमार माळी इस प्री-इवेंट में सासन गिर में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से आगामी 1 और 2 जून को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली समिट आयोजित होगी। इस समिट की प्री-इवेंट्स देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग थीम पर आयोजित की जाएंगी। इसके अंतर्गत सासन गिर में सिंह, भोपाल में चीता, भुवनेश्वर में तेंदुआ, गंगटोक में स्नो लेपर्ड तथा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने सासन गिर की इस प्री-इवेंट को बिग कैट संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के विजन को समझने का उत्कृष्ट स्थल बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने

गिर अभयारण्य और सिंहों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए, उनके अनुभव से देश में बिग कैट संरक्षण को नई गति मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी के साथ इमोशन जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण गुजरात में चरितार्थ हुआ है।

सिंह संरक्षण को प्राथमिकता और वन विभाग की बेस्ट प्रो एक्टिव प्रेक्टिसिस के परिणामस्वरूप सिंहों की संख्या 1991 में 284 से बढ़कर आज लगभग 891 हो गई है।

इतना ही नहीं; सिंहों के विचरण क्षेत्र का विस्तार भी पिछले ढाई दशकों में तीन जिलों से बढ़कर 11 जिलों तक पहुंच गया है। पोरबंदर के बरडा क्षेत्र में सिंहों का प्राकृतिक आगमन हुआ है और सरकारी प्रयासों से बरडा अभयारण्य एशियाटिक लायन का नया आवास बन चुका है। वर्तमान में लगभग 24 सिंह बरडा में निवास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विस्तृत भूमिका दी कि वनराज की गौरवशाली विरासत को बनाए रखने और वन्यजीवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2000 करोड़ रुपए की 'प्रोजेक्ट लायन' योजना शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि सिंहों के लिए ब्रीडिंग सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, उपचार केंद्रों का आधुनिकीकरण, रेडियो कॉलर और ड्रोन सर्विलांस जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रोजेक्ट लायन' केवल सिंह संरक्षण ही नहीं बल्कि 'बृहद गिर' क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा स्थानीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आयोजित यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए 'जीव में शिव' तथा 'पौधों में परमात्मा' की भारतीय संस्कृति का विश्व को परिचय कराएगी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव

केंद्रीय वन और पर्यावरण तथा जलवायु मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट के संदर्भ में कहा कि, भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नया विजन प्रस्तुत किया है।

बिग कैट अर्थात बिल्ली कुल के प्रमुख वन्य प्राणियों सहित अन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट के माध्यम से मंथन किया जाएगा और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आधार स्तंभ के रूप में 'दिल्ली डिक्लेरेशन' भी जारी किया जाएगा।

इस समिट में विश्व के नीति-निर्माता, वन्यजीव क्षेत्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, कॉर्पोरेट जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग भाग लेंगे। इससे वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सहयोग और अधिक सुदृढ़ बनेगा।

इस समिट की थीम भी बिल्ली कुल के वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा मानवता और पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण पर आधारित रहेगी।

उन्होंने उद्घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की परिकल्पना और पहल वर्ष 2023 में की गई थी। अब 1 जून 2026 को उनके मार्गदर्शन में आईबीसीए शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। बिल्ली कुल की ये सात प्रजातियां विश्व के 55 देशों में पाई जाती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात ने पूरे विश्व के सामने सिंह संरक्षण का उत्कृष्ट रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। जबकि पूरे विश्व में अफ्रीकी लायन सहित अन्य सिंहों की संख्या घट रही है, वहीं एशियाई शेरों की आबादी में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 891 हो गई है। सिंहों के संरक्षण के लिए नए आवास क्षेत्र भी विकसित किए गए हैं, जिनमें बरडा अभयारण्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया है। सौराष्ट्र और गुजरात की जनता के सम्मान के प्रतीक बने सिंह तथा उनके संरक्षण के इस मॉडल को हम पूरे विश्व के सामने आगे बढ़ाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि मनुष्य हर वस्तु का निर्माण कर सकता है, लेकिन जीव का निर्माण नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति भी करुणा के गुण पर विशेष बल देती है, अर्थात पूरी पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त जीव-जगत के लिए भी है, इसलिए उसका संरक्षण करना उतना ही आवश्यक है।

उन्होंने प्रगति के लिए आर्थिक विकास के साथ-साथ इकोसिस्टम के संरक्षण पर भी बल देते हुए कहा कि जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है।

इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने सासन की भूमि पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्री-इवेंट आयोजित किए जाने का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात की धरती पर बिल्ली कुल के प्रमुख वन्य प्राणी जैसे सिंह और तेंदुआ पहले से ही पाए जाते हैं, और अब इसमें वृद्धि करते हुए रतन महाल अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति भी देखी गई है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बाघ का गुजरात की धरती पर स्थायी निवास सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चीते को भी गुजरात में लाने की तैयारी वन विभाग द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में पर्यावरण संरक्षण के साथ इकोसिस्टम भी मजबूत हुआ है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के निदेशक एस.पी. यादव ने वीडियो फिल्म प्रस्तुति के माध्यम से आईबीसीए की पृष्ठभूमि तथा बिल्ली कुल के सात प्रमुख वन्य प्राणियों की वैश्विक उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व के सात बिग कैट में बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल हैं। इनमें से पांच — बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं।

सासन गिर में आयोजित इस प्री-इवेंट में सासन की वन्य जीव-सृष्टि और संरक्षण से संबंधित ब्रोशर का विमोचन भी किया गया।

इस अवसर पर वन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर सचिव श्री आर.सी. मीणा, डॉ. ए.पी. सिंह, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉ. जयपाल सिंह, बी.पी. पाटी, श्री रमेश कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीसीएफ डॉ. राम रतन नाला के मार्गदर्शन में सासन वन विभाग की टीम ने पूरे कार्यक्रम का समन्वय किया।

फियो ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की यूएई और यूरोप की बहु-राष्ट्रीय यात्रा का स्वागत किया, भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई

नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने 15-20 मई, 2026 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आगामी आधिकारिक यात्रा का स्वागत किया है। फियो ने कहा कि यह यात्रा प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी को काफी मजबूत करेगी और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है, जब भारत बेहतर व्यापारिक साझेदारियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश-आधारित विकास के माध्यम से यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक एकीकरण को गहरा कर रहा है।

श्री रल्हन ने कहा, " यूएई और प्रमुख यूरोपीय देशों के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की उच्च-स्तरीय वार्ताएं एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार और वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करती हैं। इस यात्रा से

इंजीनियरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा होने की उम्मीद है।"

यूएई की प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध तेजी से बढ़ते व्यापार और निवेश संपर्कों के साथ एक मजबूत 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूएई भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक बना हुआ है और मध्य पूर्व तथा अफ्रीका में भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का काम करता है।

उन्होंने आगे कहा, "यह यात्रा भारत-यूएई के आर्थिक संबंधों को विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, बुनियादी ढांचे, निवेश और सेवाओं के व्यापार के क्षेत्रों में और मजबूत करेगी। यूएई में रहने वाला विशाल भारतीय समुदाय भी व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है।"

नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में प्रधानमंत्री की वार्ताओं पर टिप्पणी करते हुए, फियो अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप भारत के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात स्थलों और निवेश के स्रोतों में से एक बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हाल ही में संपन्न हुए भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते और भारत-इएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) की पृष्ठभूमि में इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

श्री रल्हन ने कहा, "यूरोपीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की चर्चाओं से ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, एआई, इनोवेशन, स्वच्छ तकनीकें, रक्षा निर्माण, ब्लू इकॉनमी, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं और सस्टेनेबिलिटी जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों और उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं।"

ओस्लो में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि नॉर्डिक क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तकनीकों, समुद्री क्षेत्रों, डिजिटल इनोवेशन और उन्नत निर्माण में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, "भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ता रणनीतिक तालमेल भारतीय व्यवसायों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी साझेदारियों के लिए नए रास्ते खोल सकता है, साथ ही भारत के सतत और हरित विकास की ओर परिवर्तन में भी सहायता कर सकता है।"

फियो ने उद्योग के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन और भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन सहित प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री की भागीदारी का स्वागत किया और कहा कि इस तरह की बातचीत से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और मजबूत औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

श्री रल्हन ने आगे कहा, "इस यात्रा के दौरान शामिल देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार सामूहिक रूप से 70 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि इन क्षेत्रों से भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। यह यात्रा द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।"

फियो अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को और बढ़ाएगी, भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करेगी और देश के दीर्घकालिक निर्यात विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देगी।

पश्चिम रेलवे मुंबई और गोरखपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन,दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई एवं गोरखपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी तथा दो मौजूदा स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09157/09158 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर–बोरीवली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से रविवार, 17 मई, 2026 को 00.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर–बोरीवली स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से सोमवार, 18 मई, 2026 को 20.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा बुधवार को 11.30 बजे बोरीवली पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन मार्ग में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली

सिटी, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती तथा खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर–बोरीवली स्पेशल ट्रेन गोरखपुर और बोरीवली के बीच समान मार्ग के स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेनों के फेरे विस्तारित

1. ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 20 मई, 2026 को चलाया जाएगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम–मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 21 मई, 2026 को चलाया जाएगा।

2. ट्रेन संख्या 09447/09448 अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद–पटना स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 20 मई, 2026 को चलाया जाएगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09448 पटना–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का एक अतिरिक्त फेरा 22 मई, 2026 को चलाया जाएगा।

ट्रेन संख्या 09157 तथा ट्रेन संख्या 09075 एवं 09447 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 15.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी परिवार रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी परिवारों के घरों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं योजनाएं

गांधीनगर : दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (एसओयू) के आसपास रहने वाले लगभग 1000 आदिवासी परिवार रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हैं। राज्य सरकार द्वारा 1000 आदिवासी परिवारों को बायोगैस प्लांट प्रदान करने के लिए की गई मेहनत अब रंग ला रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2025 में एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी घरों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी।

यह योजना नर्मदा जिले की गरुड़ेश्वर तहसील की 38 ग्राम पंचायतों के 89 गांवों में लागू की जा रही है। गरुड़ेश्वर तहसील पंचायत द्वारा क्रियान्वित इस योजना की निगरानी जिला ग्राम विकास एजेंसी (डीआरडीए) द्वारा की जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य एलपीजी और परंपरागत लकड़ी के ईंधन पर निर्भरता को कम करना है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 7 किमी दूर स्थित वाघपुरा गांव निवासी रवि तड़वी ने कहा कि सरकार द्वारा स्थापित किए गए बायोगैस प्लांट के कारण उनके दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव आया है।

रवि तड़वी ने आगे कहा, "अब हमें एलपीजी सिलेंडर की चिंता नहीं रहती। बायोगैस प्लांट के जरिए रोजाना स्वच्छ ईंधन मिलता है और बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी खेती में रासायनिक खाद का उत्तम विकल्प बन गई है। जैविक खाद के उपयोग के कारण फसल का उत्पादन भी अधिक होता है।"

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए स्थानीय निवासी चंदू तड़वी ने योजना से महिलाओं के जीवन पर पड़े सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया, "बायोगैस प्लांट के कारण महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है। पहले वे खेत में काम

करने के बाद लकड़ी इकट्ठा करने के लिए दूरदराज के स्थानों तक जाती थीं। चूल्हे पर रसोई पकाने के कारण धुआं निकलता था और आंखों को नुकसान होता था। लेकिन, अब बायोगैस के उपयोग के कारण उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है और वे रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन गई हैं।"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। गुजरात में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए काफी प्रयास किए गए हैं।

अब तक 665 से अधिक बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और बाकी प्लांट लगाने का काम प्रगति पर है। प्लांट को स्थापित करने का पूरा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है। लाभार्थी को प्लांट स्थापित करने के लिए जरूरी गड्ढा खोदने के लिए श्रमदान करना होता है।

बायोगैस प्लांट से महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस मिलती है, साथ ही प्लांट से निकलने वाली स्लरी का उपयोग खेती में खाद के रूप में होने से विदेश से आयात होने वाले रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होती है।

सूरत एयरपोर्ट को वैश्विक उड़ान केंद्र बनाने की कवायद तेज : दिल्ली में केंद्रीय मंत्री संग एसजीसीसीआई की बड़ी बैठक, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी पर जोर

Surat को देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों में गिना जाता है, लेकिन लंबे समय से शहर के उद्योग और व्यापार जगत की एक बड़ी मांग यह रही है कि यहां का एयरपोर्ट भी उसी स्तर की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी हासिल करे, जिसकी आवश्यकता तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को है। अब इस दिशा में प्रयास तेज होते दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली में Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry यानी एसजीसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री Kinjarapu Ram Mohan Naidu से मुलाकात कर सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार, एयर कनेक्टिविटी और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस महत्वपूर्ण बैठक को दक्षिण गुजरात के औद्योगिक विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और नवसारी सांसद C. R. Patil की विशेष मध्यस्थता और समन्वय से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर किया गया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस दौरान सूरत की आर्थिक क्षमता, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यात्रियों की जरूरतों को सामने रखते हुए एयरपोर्ट विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसजीसीसीआई के प्रेसिडेंट-डेजिग्नेट Ashok Jirawala ने किया। उन्होंने प्रस्तुति के दौरान कहा कि सूरत केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। डायमंड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और एमएसएमई सेक्टर में सूरत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों के साथ यहां के उद्योगों का सीधा व्यापारिक संबंध है, लेकिन इसके बावजूद एयर कनेक्टिविटी अभी

भी शहर की जरूरतों के अनुरूप विकसित नहीं हो पाई है।

एसजीसीसीआई ने सबसे महत्वपूर्ण मांग सूरत को एयर सर्विस एग्रीमेंट यानी एएसए के तहत "पॉइंट ऑफ कॉल" घोषित करने की रखी। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यदि सूरत को यह दर्जा मिलता है, तो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को सीधे यहां से उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी। इससे शहर को वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क से सीधे जोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी और यात्रियों को मुंबई जैसे दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

बैठक में विशेष रूप से सूरत-दुबई, शारजाह और बैंकॉक जैसी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। उद्योगपतियों ने कहा कि इन रूट्स पर पहले अच्छी यात्री संख्या मिलती रही है और आज भी इन शहरों के लिए भारी मांग मौजूद है। दक्षिण गुजरात के बड़ी संख्या में व्यापारी, एनआरआई और प्रवासी समुदाय के लोग नियमित रूप से इन मार्गों पर यात्रा करते हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली व्यापार और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

घरेलू कनेक्टिविटी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रतिनिधिमंडल ने सूरत और Mumbai के बीच दैनिक उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मांग की। साथ ही Delhi सेक्टर में अतिरिक्त फ्लाइट फ्रीक्वेंसी शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया। उद्योग संगठनों का कहना है कि सूरत से रोजाना बड़ी संख्या में कारोबारी और यात्री इन दोनों महानगरों की यात्रा करते हैं, लेकिन वर्तमान उड़ानें मांग के मुकाबले पर्याप्त नहीं हैं।

इसके अलावा सूरत से Bhubaneswar के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि ओडिशा और गुजरात के बीच श्रमिकों और औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा संबंध है, इसलिए यह कनेक्टिविटी सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से आवश्यक है। चैंबर ने जोधपुर, जैसलमेर, रांची, पटना, वाराणसी, कोच्चि, कोयंबटूर, इंदौर और लखनऊ जैसे शहरों के लिए भी सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत अतिरिक्त उड़ानों और नए UDAN रूट्स को मंजूरी देने का आग्रह भी किया गया। उद्योग जगत का मानना है कि बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से न केवल व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि पर्यटन और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।

बैठक में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सूरत एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एक साथ संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शहर के निर्यातकों को राहत देने के लिए पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। उद्योगपतियों ने कहा कि वर्तमान में बड़ी मात्रा में निर्यात सामग्री मुंबई भेजनी पड़ती है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। यदि सूरत में आधुनिक कार्गो सुविधा विकसित होती है, तो निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी।

खराब मौसम के दौरान उड़ानों में देरी और बाधाओं को कम करने के लिए CAT-I लैंडिंग सिस्टम और एडवांस्ड अप्रोच लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ड्यूटी-फ्री शॉप्स शुरू करने तथा पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का सुझाव भी दिया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट मास्टर प्लान-2047 को लेकर भी चर्चा की। प्रस्तुति में बताया गया कि वर्ष 2023 में सूरत एयरपोर्ट पर 25,520 वर्गमीटर का आधुनिक टर्मिनल विकसित किया गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 55 लाख यात्रियों की है। एयरपोर्ट पर 24x7 संचालन और नाइट पार्किंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एयरपोर्ट को इस स्तर तक विकसित करने की योजना है कि वर्ष 2047 तक यहां हर साल 2.25 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता विकसित की जा सके।

बैठक में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एयरसाइड ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने का सुझाव भी दिया गया। इसे भविष्य के टिकाऊ और आधुनिक एयरपोर्ट मॉडल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने सूरत की आर्थिक क्षमता और एयर ट्रैफिक की बढ़ती जरूरतों को स्वीकार करते हुए आवश्यक स्तर पर सकारात्मक विचार और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सूरत मेट्रो ने बढ़ाई रफ्तार : दूसरे कॉरिडोर पर ट्रायल रन शुरू, शहर को जल्द मिल सकती है आधुनिक यातायात की नई पहचान

तेजी से विकसित हो रहे Surat में बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना अब अपने निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। वर्षों से जिस परियोजना को शहर के भविष्य की यातायात व्यवस्था का आधार माना जा रहा था, वह अब जमीन पर वास्तविक रूप लेने लगी है। पहले कॉरिडोर पर सफल परीक्षणों के बाद अब दूसरे कॉरिडोर पर भी मेट्रो ट्रेन का आधिकारिक ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। इस नई प्रगति ने यह संकेत दे दिया है कि सूरत में मेट्रो सेवा शुरू होने का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं रह सकता।

गुरुवार को उगत कैनाल रोड से दूसरे कॉरिडोर के ट्रायल रन की औपचारिक शुरुआत हुई। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि शहर के सार्वजनिक परिवहन इतिहास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रायल रन के दौरान मेट्रो ट्रेन को लगभग 500 घंटे तक लगातार अलग-अलग परिस्थितियों में चलाया जाएगा। इस दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक की स्थिरता, सिग्नलिंग, बिजली आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था और संपूर्ण ऑपरेशनल सिस्टम की गहन जांच की जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी Gujarat Metro Rail Corporation यानी जीएमआरसी और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम कर रही है। परियोजना से जुड़े इंजीनियरों के अनुसार, ट्रायल रन का उद्देश्य केवल ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मेट्रो प्रणाली यात्रियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद हो। हर तकनीकी पहलू का अलग-अलग स्तर पर परीक्षण किया जाएगा ताकि भविष्य में संचालन के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए।

अधिकारियों के मुताबिक ट्रायल रन पूरा होने के बाद देश की प्रमुख तकनीकी संस्था Research Designs and Standards Organisation यानी आरडीएसओ द्वारा विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य नियामक एजेंसियां भी परियोजना की सुरक्षा और संचालन क्षमता की जांच करेंगी। अंतिम चरण में Commissioner of Metro Rail Safety यानी सीएमआरएस की ओर से सुरक्षा निरीक्षण और मंजूरी दी जाएगी। इन सभी परीक्षणों और स्वीकृतियों के बाद ही सूरत मेट्रो आम यात्रियों के लिए शुरू की जाएगी।

सूरत मेट्रो परियोजना को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परिवहन परियोजनाओं में गिना जा रहा है। लगभग 12,020 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की कुल लंबाई 40.35 किलोमीटर है। इसमें दो बड़े कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो शहर के अलग-अलग हिस्सों को तेज, आधुनिक और सुगम यातायात सुविधा से जोड़ेंगे। जीएमआरसी के अनुसार, परियोजना का अब तक 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, जो इस बात का संकेत है कि निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।

पूरी परियोजना के तहत कुल 38 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दो बड़े डिपो — ड्रीम सिटी डिपो और भेसन डिपो — भी विकसित किए गए हैं, जहां मेट्रो ट्रेनों का रखरखाव और तकनीकी संचालन होगा। इन डिपो को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि भविष्य में बढ़ती यात्री संख्या और परिचालन आवश्यकताओं को आसानी से संभाला जा सके।

इससे पहले 29 मार्च 2026 को पहले कॉरिडोर यानी नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर पर ट्रायल रन शुरू किया गया था। इस कॉरिडोर में ड्रीम सिटी से अलथान टेनेमेंट स्टेशन तक लगभग 8.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। इस रूट में कुल सात स्टेशन शामिल हैं और वहां फिलहाल तकनीकी वेरिफिकेशन तथा सुरक्षा परीक्षणों की प्रक्रिया जारी है।

अब दूसरे कॉरिडोर यानी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर भी सिविल कार्य पूरा होने के बाद ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इस कॉरिडोर की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है और इसमें सात नए स्टेशन शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे कॉरिडोर के परीक्षण शुरू होने से परियोजना की प्रगति को नई गति मिली है और इससे मेट्रो सेवा शुरू होने की समयसीमा भी पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट होती दिखाई दे रही है।

सूरत जैसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक और व्यावसायिक शहर के लिए मेट्रो परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हीरा और वस्त्र उद्योग के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध यह शहर पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या और यातायात दबाव दोनों के मामले में तेजी से बढ़ा है। बढ़ती आबादी, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के बीच मेट्रो सेवा को आधुनिक और टिकाऊ परिवहन समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

शहर के नागरिकों को उम्मीद है कि मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद यात्रा का समय कम होगा, सड़क यातायात का दबाव घटेगा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुविधाजनक बनेगी। खासकर रोजाना काम पर आने-जाने वाले हजारों लोगों के लिए यह परियोजना बड़ी राहत साबित हो सकती है। इसके अलावा मेट्रो के शुरू होने से शहर के रियल एस्टेट, व्यापार और शहरी विकास को भी नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सूरत मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की शहरी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बढ़ती जनसंख्या और यातायात आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। स्टेशन परिसरों, यात्री सुविधाओं, डिजिटल टिकटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

हालांकि अभी परियोजना के कुछ हिस्सों में निर्माण और परीक्षण कार्य बाकी है, लेकिन दूसरे कॉरिडोर पर ट्रायल रन शुरू होने के बाद यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि सूरत अब मेट्रो युग में प्रवेश करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। आने वाले महीनों में यदि सभी तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मंजूरियां समय पर पूरी हो जाती हैं, तो शहरवासियों का वर्षों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो सकता है।

सूरत की पहचान अब केवल उद्योग और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था वाले देश के प्रमुख शहरों में भी उसका नाम शामिल होने जा रहा है। मेट्रो परियोजना की बढ़ती रफ्तार ने यह उम्मीद जगा दी है कि जल्द ही शहर की सड़कों के ऊपर दौड़ती आधुनिक ट्रेनें सूरत के विकास की नई तस्वीर पेश करेंगी।

NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देशभर में लाखों छात्र हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में अथक परिश्रम करते हैं, उज्ज्वल भविष्य के सपने लिए हुए। लेकिन जब इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें सामने आती हैं या पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। इस साल भी, मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर पेपर लीक के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 3 मई को होने वाली परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा, मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

यहां सवाल यह उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार अनियमितताएं क्यों होती हैं? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का दावा है कि प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर उन्हें संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने तक पूरी गोपनीयता बरती जाती है। साथ ही, सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है। ऐसे में, परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों के एक विशिष्ट समूह तक कैसे पहुंच जाते हैं? ये बातें क्या संकेत देती हैं? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और जांच एजेंसियां अनियमितताओं के इस बार-बार होने वाले चक्र के मूल कारण या विशिष्ट खामी का पता लगाने में असमर्थ क्यों हैं?

स्पष्टतः, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, उससे जुड़े अन्य संगठनों और "पेपर लीक माफिया" के बीच सांठगांठ के बिना ऐसी घटनाएं संभव नहीं हैं। सरकार को इन परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों द्वारा की गई अथक मेहनत पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वास्तव में, कई परिवार महंगे कोचिंग कार्यक्रमों के लिए अपनी जमीन या गहने तक गिरवी रख देते हैं, जबकि कई छात्र बैंक से ऋण लेते हैं। इसलिए, प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इन छात्रों का भविष्य खतरे में न पड़े।

राजस्थान के दो भाइयों को 30 लाख रुपये में NEET-UG परीक्षा का पेपर खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने बेटे के लिए गुरुग्राम के एक डॉक्टर से यह सौदा किया था। NEET-UG परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान से दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों ने परीक्षा से पहले गुरुग्राम के एक डॉक्टर से यह पेपर प्राप्त किया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के जामवा रामगढ़ निवासी मंगिलाल और दिनेश बिवाल ने परीक्षा से पहले 26 अप्रैल को 30 लाख रुपये में यह पेपर खरीदा था। इनमें से एक भाई ने यह पेपर अपने बेटे को दिया, जो राजस्थान के सीकर में मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

29 तारीख को यह पेपर एक और छात्र को बेचा गया और उसके बाद यह पेपर हर जगह फैल गया। यह भी सामने आया है कि इन भाइयों में से एक के राजनीतिक संबंध हैं। वह डॉक्टर कौन है? रहस्य अभी भी बना हुआ है। एमबीबीएस मेडिकल में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलता है जो विज्ञान विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और अच्छे अंकों से NEET परीक्षा पास करते हैं। और इस मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए NEET में भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। और मेडिकल में शॉर्टकट के तौर पर प्रवेश पाने के लिए, कुछ माता-पिता लाखों रुपये खर्च करके NEET के पेपर खरीदते हैं ताकि उनके बच्चे डॉक्टर बन सकें। छात्र पूरी तरह निर्दोष हैं लेकिन उनके माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए ऐसे अवैध कृत्यों का सहारा लेते हैं। यह भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है?

बारहवीं की परीक्षा में वही विषय होते हैं जो NEET परीक्षा में होते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर NEET के बिना बारहवीं की परीक्षा के नतीजों के आधार पर MBBS और मेडिकल में दाखिला दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर बारहवीं में अच्छे नंबर आए हैं तो NEET में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर बारहवीं में साइंस में कम नंबर आए हों और मेडिकल में जाना चाहते हों तो NEET जैसी भ्रष्ट परीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। क्या NEET परीक्षा से पहले दाखिला लेकर डॉक्टर बने लोग होशियार नहीं थे?

पेट्रोल–डीजल की कमी, वाहनों की लंबी कतारें और ग्राहकों पर बढ़ते दबाव के कारण सूरत में आधे पेट्रोल पंप बंद हो गए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर और जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण सरकारी तेल कंपनियों के आधे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं और पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें फिर से देखी जा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए दक्षिण गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सूरत जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सूरत कलेक्टर ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों को बुलाकर मामले का संज्ञान लिया और आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि, निजी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के कारण, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सरकारी पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई।

इसी वजह से पिछले तीन दिनों से सरकारी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। सूरत शहर और जिले के आधे से अधिक पेट्रोल पंप बंद हैं और बाकी बचे पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है।

यह जानकारी मिली है कि इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए, आपूर्ति अधिकारी ने प्रत्येक अधिकारी से उस क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर मौजूद वस्तुओं की स्टॉक सूची का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट भी मांगी है।

पश्चिम रेलवे द्वारा 15/16 मई 2026 की रात्रि में मेजर ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा दादर स्टेशन पर अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कमीशनिंग कार्य हेतु 15/16 मई, 2026 की मध्यरात्रि को मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक 15/16 मई, 2026 की मध्यरात्रि 00.00 बजे से 05.00 बजे तक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान सभी धीमी लाइन की ट्रेनें मुंबई सेंट्रल एवं माहिम स्टेशनों के बीच फास्ट लाइनों पर चलाई जाएंगी। परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता तथा प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण ये ट्रेनें महालक्ष्मी, लोअर परेल, प्रभादेवी, माटुंगा रोड एवं माहिम स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी।

उपरोक्त स्टेशनों तक यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु चर्चगेट से 23.31 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या BA91021 चर्चगेट – बांद्रा, डाउन दिशा की अंतिम ट्रेन होगी, जिसे विरार तक विस्तारित किया जाएगा। इसी प्रकार, बोरीवली से 23.03 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या BO90982 प्रभावित स्टेशनों हेतु अप दिशा की अंतिम ट्रेन होगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। प्रभावित सेवाओं की विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें।

मदार–पालनपुर रेलखंड पर ब्रिज कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा

उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर रेल मंडल के मदार–पालनपुर रेलखंड पर आउवा एवं भिंवालिया स्टेशनों के मध्य स्थित ब्रिज संख्या 605 पर आरसीसी बॉक्स डालने हेतु आवश्यक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

- ट्रेन सं. 14822 साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस दिनांक 15.05.2026 और 16.05.2026 को रद्द रहेगी।
- ट्रेन सं. 14821 जोधपुर–साबरमती एक्सप्रेस, दिनांक 14.05.2026 और 15.05.2026 को रद्द रहेगी।

- दिनांक 15.05.2026 की ट्रेन सं. 19223, साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाणा–भीलड़ी–लूणी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 15.05.2026 की ट्रेन सं. 12462, साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाणा–भीलड़ी–लूणी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 15.05.2026 की ट्रेन सं. 14707, हनुमानगढ़–दादर रणकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया लूणी–भीलड़ी–मेहसाणा चलेगी।
- दिनांक 14.15.2026 की ट्रेन सं. 20496, हडपसर-जोधपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-भीलड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 14.15.2026 की ट्रेन सं. 20943, बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-भीलड़ी-लूनी के रास्ते चलेगी।
- दिनांक 14.05.2026 की ट्रेन सं. 14701, श्रीगंगानगर–बान्द्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस, परिवर्तित मार्ग अजमेर–चित्तौड़गढ़–रतलाम–वडोदरा के रास्ते चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सूरत से असम तक सेवा का सेतु : 1100 जनजातीय बेटियों के सामूहिक विवाह से जुड़ी संवेदना, संस्कार और सामाजिक एकता की अनोखी मिसाल

Surat की सामाजिक और दानशील परंपरा ने एक बार फिर देश के दूरस्थ हिस्सों तक अपनी मानवीय संवेदनाओं का विस्तार किया है। सेवा, संस्कार और सामाजिक सहयोग की भावना को केंद्र में रखते हुए सूरत की सामाजिक संस्था Purvanchal Samuhik Vivah Anushthan Samiti ने असम के जनजातीय क्षेत्रों में 1100 बेटियों के सामूहिक विवाह का विशाल आयोजन कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। यह आयोजन केवल विवाह संस्कार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण और जरूरतमंद परिवारों के सहयोग के बड़े अभियान के रूप में देखा जा रहा है।

संस्था द्वारा वर्षों से पूर्वोत्तर भारत के दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में सेवा कार्य किए जाते रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष असम के चाय बागानों और जनजातीय इलाकों में रहने वाले परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन का उद्देश्य उन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहारा देना था, जिनके लिए पारंपरिक विवाह आयोजन करना कठिन हो जाता है।

कार्यक्रम का संचालन धर्मजागरण समन्वय-सूरत विवाह समिति के प्रमुख Vijay Kumar Chaumal के नेतृत्व में किया गया, जबकि संस्था के संरक्षक Rakesh Kansal का विशेष सहयोग रहा। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार, इस सेवा कार्य का मूल उद्देश्य केवल विवाह संपन्न कराना नहीं, बल्कि जनजातीय समाज में आत्मविश्वास, सम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना भी है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम असम के कई महत्वपूर्ण जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए। इनमें Tezpur, Tinsukia, Jorhat तथा Karbi Anglong जैसे इलाके प्रमुख रहे। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो आर्थिक सीमाओं के कारण बेटियों के विवाह को लेकर लंबे समय तक संघर्ष करते हैं। संस्था ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जोड़ा।

आयोजन के दौरान विवाह संस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक विधियों के अनुसार संपन्न कराए गए। स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, ताकि विवाह केवल औपचारिक कार्यक्रम न रहकर सामाजिक उत्सव का रूप ले सके। कई गांवों में इस आयोजन को लेकर उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया और स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक सहयोग की बड़ी पहल बताया।

इस सेवा अभियान में प्रत्यक्ष भागीदारी और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सूरत से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भी असम पहुंचा। चार दिवसीय प्रवास के दौरान राकेश कंसल, उनकी धर्मपत्नी प्रीति बहन, विजय चौमाल तथा Balkishan Agrawal सहित कई पदाधिकारी विभिन्न विवाह स्थलों पर मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय परिवारों से मुलाकात कर उनकी परिस्थितियों को समझा और आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

क्रूड ऑयल वायदा 62 रुपये फिसला: सोना वायदा में 44 रुपये का सुधार: चांदी वायदा में 4357 रुपये की गिरावट

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 498403.99 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 34481.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 463921.72 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 40063 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4222.45 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 23754.47 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 161888 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 163055 रुपये और नीचे में 161027 रुपये पर पहुंचकर, 162186 रुपये के पिछले बंद के सामने 44 रुपये या 0.03 फीसदी की तेजी के संग 162230 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मई वायदा 55 रुपये या 0.04 फीसदी औंधकर 130068 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 8 रुपये या 0.05 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 16294 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 161387 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162389 रुपये और नीचे में 159526 रुपये पर पहुंचकर, 99 रुपये या 0.06 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 161656 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 161720 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162551 रुपये और नीचे में 158200 रुपये पर पहुंचकर, 161723 रुपये के पिछले बंद के सामने 197 रुपये या 0.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 161920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 298373 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 299000 रुपये और नीचे में 294450 रुपये पर पहुंचकर, 300238 रुपये के पिछले बंद के सामने 4357 रुपये या 1.45 फीसदी औंधकर 295881 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 3703 रुपये या 1.23 फीसदी की गिरावट के साथ 298431 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 3806 रुपये या

1.26 फीसदी लुढ़ककर 298351 रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 4995.77 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 4.9 रुपये या 0.35 फीसदी घटकर 1394 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 5.1 रुपये या 1.4 फीसदी बढ़कर 369.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 65 पैसे या 0.17 फीसदी की नरमी के साथ 385.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 30 पैसे या 0.15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 204.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कमोडिटी वायदाओं में 34481.06 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 463921.72 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 23754.47 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40063 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5551.75 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9706 रुपये के भाव पर खूलकर, 9804 रुपये के दिन के उच्च और 9541 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 62 रुपये या 0.64 फीसदी की गिरावट के साथ 9649 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 65 रुपये या 0.67 फीसदी लुढ़ककर 9646 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 272 रुपये के भाव पर खूलकर, 278.3 रुपये के दिन के उच्च और 271.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 275.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.1 रुपये या 0.76 फीसदी गिरकर 273.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 2.1 रुपये या 0.76 फीसदी औंधकर 273.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 998 रुपये पर खूलकर, 3 रुपये या 0.3 फीसदी घटकर 994 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12368.03 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 11386.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3753.49 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 566.79 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 44.85 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 617.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4118.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1411.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.72 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10974 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62951 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20886 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 269158 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 42491 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8782 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21345 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 68629 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17494 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26519 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा 40038 पॉइंट पर खूलकर, 40063 के उच्च और 40038 के नीचले स्तर को छूकर, 157 पॉइंट घटकर 40063 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 67.5 रुपये की गिरावट के साथ 70.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.1 रुपये की गिरावट के साथ 6.75 रुपये हुआ।

सोना मई 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 53 रुपये की गिरावट के साथ 236 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 318.5 रुपये की गिरावट के साथ 1596 रुपये हुआ। तांबा मई 1450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.53 रुपये की गिरावट के साथ 9.82 रुपये हुआ। जस्ता मई 415 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.99 रुपये की बढ़त के साथ 2 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 30 पैसे के सुधार के साथ 121.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 80 पैसे के सुधार के साथ 8.45 रुपये हुआ। सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 172.5 रुपये की गिरावट के साथ 581 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 73.5 रुपये की बढ़त के साथ 807.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 29 पैसे की नरमी के साथ 8.23 रुपये हुआ। जस्ता मई 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.4 रुपये की गिरावट के साथ 2.5 रुपये हुआ।